



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929

No. 346]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KAARTIKA 25, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

अंतिम जाँच परिणाम

(न्यू शिपर समीक्षा)

**विषय :-** काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सीएफएल) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मै. ओसराम चाइना लाइटिंग लि., चीन जन.गण. द्वारा अनुरोध की गई न्यू शिपर समीक्षा (पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत)

**फा. सं. 15/27/2004-डीजीएडी.**—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

**क. प्रक्रिया**

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को मै. ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चाइना (जिसे एतद्पश्चात् न्यू शिपर कहा गया है) से व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अधिसूचना सं. 34/1/2001 दिनांक 14 नवम्बर, 2002 की उपर्युक्त नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत समीक्षा की शुरुआत करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। आवेदक ने यह घोषणा की है कि वह संबंधित उत्पाद के संबंध में लागू पाटनरोधी उपायों के अधीन चीन जन.गण. के किसी निर्यातक और उत्पादक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने घोषित किया कि उन्होंने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच की है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के उपबंधों के अनुसार समीक्षा की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए उसे प्रथमदृष्टया पर्याप्त माना है।
- (ii) प्राधिकारी ने मै. ओसराम चाइना लाइटिंग लि., चीन (उत्पादक एवं निर्यातक) के अनुरोध के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. 15/27/2004-डीजीएडी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत की है।
- (iii) पूर्वोक्त न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों (सीएफएल) के आयात के मामले में शुरू की गई थी जिसमें प्राधिकारी दिनांक 14 नवम्बर, 2002 के अपने अंतिम जांच परिणाम सं. 34/1/2001 द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि :-

(सीएफएल) के आयात के मामले में शुरू की गई थी जिसमें प्राधिकारी दिनांक 14 नवम्बर, 2002 के अपने अंतिम जाँच परिणाम सं० 34/1/2001 द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि :-

- (क) चीन जन.गण. तथा हांगकांग के मूल के और वहाँ से निर्यातित सीएफएल का भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ।
  - (ख) चीन जन.गण. और हांगकांग से सीएफएल के निर्यातों से भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।
  - (ग) यह क्षति संचयी रूप से चीन जन.गण. और हांगकांग से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है ।
  - (घ) मै० फिलिप्स एण्ड यामिंग, पीआरसी द्वारा चोक के साथ सी एफ एल के निर्यातों के मामले से कारणात्मक संबंध सिद्ध नहीं किया जा सका था क्योंकि इन निर्यातों का पहुँच मूल्य क्षति रहित कीमत से अधिक था ।
- (iv) केन्द्र सरकार ने चीन जन. गण. और हांगकांग से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के आयातों संबंधी मूल जाँच में दिनांक 10.22.2002 की अधिसूचना सं० 138/2002-सीमाशुल्क द्वारा अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की तारीख अर्थात् 2 नवम्बर, 2001 से पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।
- (v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और दिनांक 10.12.2002 की अधिसूचना सं० 138/2002-सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा के पूरा होने तक मै० ओसराम चाइना लाइटिंग कं० लि०, चीन जन.गण. (उत्पादक एवं निर्यातक) द्वारा किए गए काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के सभी निर्यातों के अनंतिम आकलन की अनुशंसा की थी ।
- (vi) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13 फरवरी, 2006 को अधिसूचना सं० 7/2006-सीमाशुल्क जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के निष्कर्ष आने तक मै० ओसराम चाइना लाइटिंग कं० लि०, चीन जन.गण. द्वारा उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 853931 के अंतर्गत आने वाले काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के निर्यातों का जब भारत में आयात किया जाता है, को समीक्षा के पूरा होने तक अनंतिम आकलन के अधीन रखा जाएगा । यह भी व्यवस्था थी कि यह अनंतिम आकलन ऐसी प्रतिभूति या गारंटी के अधीन हो सकता है जिसे सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, उस कमी, यदि होई हो के भुगतान के लिए उचित समझते हों, जो यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जाँच को पूरा करने पर पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाता है तो उत्पन्न होगी । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षा के पूरा होने के बाद पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा की जाती है तो आयातक को शुल्क की उस राशि का भुगतान करना होगा जिसकी समीक्षा में सिफारिश की जाती है और जो मै ओसराम चाइना लाइटिंग कं० लि०, चीन जन.गण. द्वारा उक्त समीक्षा की शुरुआत की तारीख से भारत में आयात के समय पर निर्यातित, भारत में काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के सभी आयातों पर लगाया जाता है ।

- (vii) वर्तमान समीक्षा में शामिल विचाराधीन उत्पाद, मूल जाँच में शामिल उत्पाद के समान अर्थात् काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है।
- (viii) प्राधिकारी ने मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कं0 लि0, चीन जन.गण. (उत्पादक एवं निर्यातक) को निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली की एक-एक प्रति भेजी थी। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाने वाली सूचना मंगाई थी। प्राधिकारी ने मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कं0 लि0 (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का उनके परिसर में सत्यापन किया था।
- (ix) प्राधिकारी ने आयातक मै0 ओसराम इंडिया से आयातों, संबंधित खर्चों और पहले स्वतंत्र खरीदार को बिक्रियों के संबंध में सूचना मंगाई थी।
- (x) इस न्यू शिपर जाँच में पाटन के निर्धारण हेतु जाँच अवधि 6 माह अर्थात् 1 जनवरी, 2005 से 30 जून, 2005 है।
- (xi) प्राधिकारी ने निर्यातक देश के प्राधिकारी को न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत की सूचना आधिकारिक रूप से दी थी और सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को जाँच अवधि (अर्थात् 1 जनवरी, 2005 से 30 जून, 2005 तक) की समाप्ति से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- (xii) प्राधिकारी ने दिनांक 2.2.2006 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- (xiii) नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए, अनुरोध करने पर, उपलब्ध कराया था।
- (xiv) संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जाँच परिणामों हेतु विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधारों का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किया गया था और उन पर पाँच परिणामों में विधिवत ढंग से विचार भी किया गया है।
- (xv) इस अधिसूचना में \*\*\* चिह्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है। आवेदक द्वारा कीमत और लागत निर्धारण संबंधी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है और इन्हें प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद

2. प्राधिकारी ने मूल जाँच में यथा निर्धारित काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प के रूप में विचाराधीन उत्पाद के वर्णन को जारी रखने का निर्णय लिया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाए गए हैं।

मै0 इंडो-एशियन फ्यूज गियर लि0, (ख) मै0 फिलिप्स इंडिया लि0 और (ग) मै0 हवेल्स इंडिया लि0 के विचार

3. यह अनुरोध किया गया है कि :-

(क) न तो आवेदन में और न ही न्यू शिपर की ओर से प्रस्तुत लिखित अनुरोध में यह बताया गया है कि न्यू शिपर समीक्षा का कार्यक्षेत्र केवल कुछेक प्रकार के सीएफएल तक सीमित है और न कि सभी प्रकार के सीएफएल तक। यह निर्विवाद है किसी सीएफएल का वह प्रकार जिनका ओसराम इंडिया भारत में आयात करना चाहते हैं, भारत में विनिर्मित और बेचे जा रहे सीएफएल के प्रकारों के प्रत्यक्ष स्थानापन्न है। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादकों के पास इन घुमावदार और छोटे सीएफएल के उत्पादन की क्षमता है यद्यपि उन्होंने अभी तक इनका विनिर्माण नहीं किया है। भारत में सीएफएल के उन प्रकारों के आयात से सीएफएल के लिए भारतीय बाजार पर बुरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इस लिए होगा क्योंकि नई पीढ़ी के ये सीएफएल मौजूदा सीएफएल के बाजारों पर कब्जा कर लेंगे।

(ख) सुनवाई के दौरान न्यू शिपर के अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से कहा था कि समीक्षा का दायरा छोटे और घुमावदार सीएफएल (टी 3 लैम्पों) तक सीमित है।

(ग) तथापि लिखित अनुरोधों में ऐसी कोई घोषणा नहीं दी गई है। न्यू शिपर को स्पष्ट रूप से यह बताने के निर्देश दिए जाएं कि क्या वे सभी प्रकार के सीएफएल हेतु न्यू शिपर समीक्षा चाहते हैं या वह सीएफएल के केवल कुछेक प्रकारों तक सीमित है। यदि वह सीएफएल के कतिपय प्रकारों तक सीमित है तो सीएफएल के उन प्रकारों के नाम, विवरण और संपूर्ण विनिर्देशन तत्काल प्रस्तुत किए जाएं।

(घ) याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 22.11.2004 के अनुरोध पत्र में बताया है कि ओसराम, चीन में छोटे और घुमावदार सीएफएल का विनिर्माण करते हैं और वे चीन से भारत में इन छोटे और घुमावदार सीएफएल का निर्यात करना चाहते हैं। यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या ओसराम चाइना छोटे और घुमावदार से इतर सीएफएल के विनिर्माण में भी शामिल है। यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या न्यू शिपर सभी प्रकार के सीएफएल को शामिल करना चाहते हैं या वे केवल सीमित श्रेणी अर्थात् छोटे और घुमावदार सीएफएल के लिए न्यू शिपर समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

(ङ.) मूल जाँच के रिकार्डों से यह देखा जा सकता है कि ओसराम इंडिया ने जाँच अवधि के दौरान जर्मनी से सीएफएल का आयात किया था। यह ज्ञात नहीं है कि क्या वे सीएफएल ओसराम चाइना में विनिर्मित थे या जर्मनी के थे या कहीं और बने हुए थे। इस प्रश्न की विस्तृत जाँच किए जाने की जरूरत है।

(च) निर्यातक द्वारा यह कहा गया है कि उनकी एक संबंधित चीनी कम्पनी मै0 चुंग टाक लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम्स (पीएनओयू) लि0 ओसराम चाइना भिन्न-भिन्न प्रकार के सीएफएल का उत्पादन करती है और उनके नाम सीएफएल I, सीएफएल II, सीएफएल III आदि हैं। यह ज्ञात नहीं है कि क्या संबंधित कम्पनी सीएफएल के अन्य प्रकारों अर्थात् सीएफएल ओ II, सीएफएल III आदि के विनिर्माण में भी लगी हुई है। यह नोट करना जरूरी है कि जाँच में संबंधित उत्पाद के सभी प्रकार शामिल हैं। उत्पाद को सीएफएल -I, सीएफएल -II आदि के रूप में बताकर संबंधित उत्पाद के कार्यक्षेत्र का कोई अपवाद या अपवर्जन नहीं हो सकता है। प्राधिकारी को इस बात पर विचार किए बिना कि क्या उक्त उत्पाद सीएफएल-I है या नहीं इस बात की जाँच करने की जरूरत है कि क्या निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का आयात किया है।

### न्यू शिपर के विचार

4. ओसराम समूह द्वारा अपने भारतीय प्रचालनों के जरिए भारत में सीएफएल व्यवसाय में निवेश करना जारी है। जैसाकि पूर्व में बताया गया है समूह की नीति के अनुसार एक देश में ओसराम कम्पनी से वस्तुएं अन्य देशों को निर्यात की जाती हैं। मै0 ओसराम इंडिया लि0 लैम्प सहित कई उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात करती है।

मै0 ओसराम इंडिया लि0 का आयात करने का इरादा नहीं है और आवेदक इसकी समूह कम्पनी द्वारा बनाये गए किसी सीएफएल का भारत को निर्यात नहीं करेगा।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

5. मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित चोक या बलास्ट के साथ या इसके बगैर, एक या एक से अधिक कांच की ट्यूब्स के साथ काम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्पस (सीएफएल) था और जिसमें प्रकाश के सभी अवयव, सभी इलेक्ट्रॉनिक संघटक होते हैं और जिसकी चोटी लैम्प के आधार में लगी होती है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 8539.31 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह जांच पर बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान जाँच आवेदक मै0 ओसराम चाईना लाइटिंग लि0, चीन जन.गण. हेतु अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारणार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत केवल न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) है, इसलिए इस जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का वर्णन मूल जांच में दिए गए वर्णन के समान है जैसाकि मै0 ओसराम चाईना लाइटिंग लि0 द्वारा विनिर्माण एवं निर्यात किया गया है।

### ग. जांच शुरुआत के समय/उसके पश्चात अभिव्यक्त किए गए विचार एवं उनकी जांच

#### विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. मै0 इंडो-एशियन फ्यूज गीयर लि0, (ख) मै0 फिलिप इंडिया लि0 और (ग) मै0 हैवेल्स इंडिया लि0 के विचारों का सारांश निम्नानुसार है :-

एनएसआर का आवेदन पत्र कपटपूर्ण है और इसलिए बगैर किसी आगे की कार्रवाई के जाँच को समाप्त किया जा सकता है।

7. एक घरेलू उत्पादक के रूप में मै0 ओसराम इंडिया ने इंडो-एशियन के साथ एक याचिका दायर की थी और मौजूदा उपायों को लागू करवाया था। अब मै0 ओसराम इंडिया अपनी संबद्ध कम्पनी के लिए न्यू शिपर समीक्षा की मांग कर रही है। इससे चीन के सभी विनिर्माताओं से सीएफएल के आयात को प्रतिबंधित करने के ओसराम इंडिया के सुनियोजित प्रयास का पता चलता है और तत्पश्चात वे अपनी संबद्ध कम्पनी को बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां ओसराम चाईना के पास चीन के अन्य उत्पादकों की तुलना में स्पष्ट प्रतिस्पर्धी लाभ है।

8. समूची प्रक्रिया कपटपूर्ण प्रतीत होती है। अतः प्राधिकारी जांच को जारी नहीं रखेंगे और इसे बगैर किसी आगे की कार्रवाई के समाप्त करते हैं।

### जांच शुरूआत दोषपूर्ण है

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एनएसआर शुरू करने के लिए एक लाइन के वक्तव्य पर भरोसा किया है। निर्यातक को यह दिखाने के लिए प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना है कि उसने संगत वर्ष के दौरान वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया है। आवेदन पत्र में इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था कि आवेदक ने संगत अवधि के दौरान उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया है।

10. निर्यातक के लिए यह दिखाना अपेक्षित है कि वे निर्यातक देश में किसी अन्य उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है। न्यू शिपर ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि वे संगत अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं रहे हैं। अतः जांच शुरूआत दोषपूर्ण है।

### इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यू शिपर समीक्षा उपयुक्त कार्रवाई नहीं है।

11. नियम 22 के अनुसार किसी एनएसआर का कार्यक्षेत्र न्यू शिपर हेतु पाटन मार्जिन के निर्धारण तक सीमित है। क्षति, घरेलू उद्योग की स्थिति, आदि संबंधी किसी भी मुद्दे की जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

12. तथापि, जब कोई घरेलू उत्पादक पाटनरोधी उपाय लागू करवाने के पश्चात उत्पाद का भारत में आयात करके स्वयं को क्षति पहुँचाना शुरू कर देता है तो प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य है। प्राधिकारी साधारण रूप से नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा नहीं कर सकते हैं जो पाटन संबंधी पहलुओं तक सीमित है।

13. नियम 2 (ख) के अनुसार जब घरेलू उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उस वस्तु के आयातक हों तो ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यदि एक बार कोई घरेलू उत्पादक या इसका संबंधित निर्यातक न्यू शिपर समीक्षा की मांग करता है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात करना शुरू कर देता है तो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उक्त उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाएगा अथवा नहीं। यदि प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि उक्त उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं होगा तो घरेलू उत्पादकों द्वारा वहन की गई क्षति की सही मात्रा एवं सीमा का निर्धारण करने के लिए मौजूदा उपायों की समीक्षा किए जाने की जरूरत होती है।

14. इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या पाटन और क्षति दोनों पर विचार करने के पश्चात मौजूदा उपायों को जारी रखने या वापस लेने की जरूरत है, यह एक उपयुक्त मामला बनता है। तथापि किसी न्यू शिपर समीक्षा जांच का कार्यक्षेत्र केवल पाटन संबंधी पहलुओं तक सीमित होता है। अतः इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यू शिपर समीक्षा उपयुक्त कार्रवाई नहीं है। इसे बगैर किसी आगे की कार्यवाही के तुरंत समाप्त किए जाने की जरूरत है।

### इस मामले में ओसराम इंडिया की स्थिति का निर्धारण किए जाने की जरूरत है ।

15. लिखित निवेदनों में ओसराम इंडिया ने कारकों की एक लम्बी सूची दी है जिनकी घरेलू उद्योग के घटक के रूप में ओसराम इंडिया की स्थिति के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी अपेक्षित है । ओसराम इंडिया ने उनके द्वारा सूचीबद्ध किए गए 10 कारकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है । बगैर कोई सूचना दिए केवल कारकों की सूची देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । इसके अलावा, यदि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के एक घटक के रूप में ओसराम इंडिया की स्थिति पर विचार करना है तो केवल ये 10 कारक पर्याप्त नहीं हैं । प्राधिकारी अनेक दूसरे कारकों के संबंध में पर्याप्त सूचना की मांग कर सकते हैं ।

16. इस मामले में जांच अपरिहार्य है लेकिन नियम 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास न्यू शिपर समीक्षा में ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए शक्तियाँ नहीं है ।

17. यदि प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा को जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो ओसराम इंडिया की स्थिति के बारे में सभी संगत कारकों का पूरा ब्यौरा प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसी विस्तृत जांच के बगैर इस न्यू शिपर समीक्षा में निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता है ।

### गोपनीयता के दावों हेतु कारण नहीं दिए गए

18. न्यू शिपर ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के महत्वपूर्ण भाग की गोपनीयता का दावा किया है । न्यू शिपर का सूचना देने का दायित्व है जो गोपनीय रूप से प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु की तर्कसंगत समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होगी । यह नियम 7(2) में निहित एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक ओर कतिपय सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा करने की जरूरत और यह सुनिश्चित करने की जरूरत कि सभी पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण अवसर मिले, के बीच नियमों द्वारा बनाए गए संतुलन को प्रतिबिम्बित करता है । यह निवेदन है कि न्यू शिपर द्वारा दी गई सूचना इस मामले में उपयुक्त उत्तर के लिए अपर्याप्त है ।

19. वर्तमान आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली के उत्तर में कोई भी कारण नहीं दिया गया है । अतः न्यू शिपर द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर को खारिज किया जा सकता है अथवा न्यू शिपरों को इस बात के कारण देते हुए कि क्यों प्रत्येक मद/आंकड़े/सूचना जिनके लिए उन्होंने गोपनीयता का दावा किया है, के संबंध में गोपनीयता की जरूरत है, प्रश्नावली उत्तर का संशोधित अगोपनीय सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है ।

### निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर बिल्कुल अपर्याप्त है

20. न्यू शिपर द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर बिल्कुल अपर्याप्त है । एनएमई प्रश्नावली उत्तर पुराने प्रारूप में है । इसे नये प्रारूप में दिया जाएगा । ऐसा मालूम होता है कि न्यू शिपर ने एनएमई प्रश्नावली के साथ ज्ञापन और कम्पनी का संगम अनुच्छेद दाखिल नहीं किया है ।

21. मुख्य प्रश्नावली का उत्तर बिल्कुल अधूरा है। उनके त्रुटियाँ बतायी गई हैं। उत्तर में प्रस्तुत सूचना प्रश्नावली के विभिन्न हिस्सों के बीच सुसंगत नहीं है। बताई गई अनेक त्रुटियों के दृष्टिगत निर्यातक की लेखांकन प्रणाली और रिकार्ड कीपिंग प्रणाली विश्वसनीय मालूम नहीं होती है।

### निर्यात कीमत विश्वसनीय नहीं है

22. भारत को निर्यात कीमत निम्न कारणों से विश्वसनीय नहीं है (क) यह भारत में एक संबद्ध कम्पनी को है, और (ख) तीसरे देशों को निर्यात कीमत भारत को निर्यात कीमत से अत्यधिक कम है।

23. ऐसा मालूम होता है कि ओसराम चाईना ने अतार्किक रूप से उच्च निर्यात कीमत प्रदर्शित की है जो इस न्यू शिपर समीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ बाजार वास्तविकता को प्रतिबिम्बित नहीं करती है। इसके अलावा, दिनांक 03.10.2005 को प्रस्तुत प्रश्नावली उत्तर के मूल अगोपनीय सारांश में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि भावी आदेश न्यू शिपर समीक्षा पर निर्भर करते हैं। इस वक्तव्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि निर्यात कीमत केवल इस जांच के प्रयोजनों के लिए है और यह नियमित कीमत है जिस पर सामान्य प्रक्रिया में इसका निर्यात किया जाता।

24. धारा 9क(1) में यह बताया गया है कि निर्यात कीमतों का उन मामलों में परिकलन किया जाएगा जहाँ कोई निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहाँ निर्यातक और आयातक के बीच संबंध के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है। उक्त स्पष्टीकरण में यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामलों में निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार किया जा सकता है जिस कीमत पर आयातित वस्तुओं की पहले किसी स्वतंत्र क्रेता को बिक्री की गई है। धारा 9क(1) के स्पष्टीकरण ख के प्रावधान स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं और इसलिए प्राधिकारी नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्यात कीमत का परिकलन करेंगे।

### अन्य मुद्दे

25. एनएमई प्रश्नावली के उत्तर में न्यू शिपर्स ने बताया है कि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है। तथापि उनके खातों से अत्यधिक वित्तीय खर्च का पता चलता है। यदि उन्होंने पूर्व में ऋण लिया था जिसको जांच अवधि की समाप्ति से पूर्व चुका दिया गया है तो प्राधिकारी ऐसे ऋणों का ब्यौरा प्राप्त करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ऐसे ऋण बाजार स्थितियों के अंतर्गत प्राप्त किए गए हैं।

### न्यू शिपर के विचार

#### मूल जांच अवधि के दौरान भारत को सीएफएल के गैर-निर्यात का प्रमाण

26. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक सांचे के भीतर न्यू शिपर समीक्षा में आवेदक मूल जांच में घरेलू उद्योग के एक घटक से संबंधित हैं। वास्तव में वे उसी समूह से हैं। समूह की नीति एवं प्रथाओं के अनुसार एक ओसराम कम्पनी से निर्यात किसी दूसरे देश में ओसराम समूह की कम्पनियों को ही किए जाते हैं।



27. मूल जांच के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओसराम इण्डिया ने मूल जांच अवधि में सीएफएल का आयात नहीं किया था। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त जांच में इसकी जांच की गई थी और पुष्टि की गई थी।

28. इस न्यू शिपर समीक्षा के प्रारम्भ में आवेदक ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि निर्यात ओसराम ग्रुप के भीतर ही किए जाएंगे। वास्तव में न्यू शिपर जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यात ओसराम इण्डिया को किए गए थे, जिन्होंने आयातक प्रश्नावली विधिवत भरकर प्रस्तुत की है, जिसका सत्यापन माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने किया है।

29. आवेदक ने पुष्टि की है कि भारत को सीएफएल का निर्यात कभी किया नहीं गया और इसका अभिनिश्चय रिकार्ड में प्रस्तुत विस्तृत ब्यौरे तथा सत्यापन दौरे के दौरान किए गए सत्यापन से किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक पूर्ण सहयोग की अपनी पेशकश को दोहराता है।

30. यह निवेदन किया जाता है कि एचआर जॉनसन इण्डिया लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी से संबंधित मामले में माननीय सीस्टेट के निर्णय की व्याख्या त्रुटिपूर्ण तथा अत्यंत बोझिल है। यह देखते हुए कि कानून, भारत की डब्ल्यूटीओ वचनबद्धताओं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रावधानों तथा विगत न्याय सिद्धांतों, सभी में न्यू शिपर समीक्षाओं का प्रावधान है। सीस्टेट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं किस प्रकार निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि यह इतना बोझिल है कि सभी प्रकार की न्यू शिपर समीक्षाएँ ही समाप्त कर दी जाए। हितबद्ध विरोधी पक्षकार इस बात के निर्णायक साक्ष्य की अपेक्षा करके कि आवेदक मूल जांच अवधि के दौरान किसी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित न होने के निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत करें, ऐसी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी पूर्ति असम्भव है। इसे और स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी भी मूल जांच में प्रत्येक निर्यातक को अभिज्ञात नहीं कर सके हैं क्योंकि यह सम्भव है कि कुछ ने सहयोग नहीं किया अथवा अन्य निर्यातकों ने ट्रेडिंग कम्पनियों अथवा अन्य तृतीय पक्षों के माध्यम से निर्यात किया। इस प्रकार इसे सिद्ध कर पाना, जैसा कि हितबद्ध विरोधी पक्षकारों ने मांग की है, लगभग असम्भव है।

31. इसके विपरीत आवेदक - सार्वजनिक रूप से व्यापारित, विधिवत लेखा परीक्षित उद्यम है। कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु आवेदक ने निम्नलिखित सूचना प्रकट की है :-

- इसकी सभी सम्बद्ध कम्पनियाँ
- इसके सभी निर्यात
- शपथ लेकर कहा कि सभी प्रकटन परिपूर्ण हैं, और
- माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपर्युक्त सभी तथा अन्य समुचित आंकड़ों के सत्यापन हेतु आमंत्रित करता है।

32. उपर्युक्त के मद्देनजर सादर निवेदन किया जाता है कि इस मामले के तथ्यों के संबंध में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रमाण संबंधी मानक समुचित तथा विधि सम्मत हैं।

### गोपनीयता का दावा

33. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की अपेक्षानुसार आवेदक ने गोपनीयता के व्यवहार के संबंध में कारण प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध के संबंध में विस्तृत कारण देते हुए एक विस्तृत पत्र भेजा गया था, जो माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

### आंकड़ों में त्रुटियां तथा अपूर्ण एमईटी प्रश्नावली

34. निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 14 फरवरी, 2006 के पत्र में किए गए अनुरोध के अनुसार आवेदक ने विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिनमें हितबद्ध विरोधी पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित अनेक मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था, जो रिकार्ड में दर्ज है।

### निर्यात कीमत

35. जहाँ तक अविश्वसनीय निर्यात कीमतों से संबंधित आरोप का प्रश्न है, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसी उत्पाद से संबंधित मूल जांच में इस मुद्दे पर विचार किया था और आवेदक को विश्वास है कि इस मामले के तथ्यात्मक सन्दर्भ में यह समुचित होगा।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

36. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत पाटनरोधी नियमावली के उपबंधों, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है, के मद्देनजर की गई थी :-

(क) नियम 22 : यदि कोई उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों के अधधीन हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रश्नागत निर्यातक देश के निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच अवधि के दौरान उस उत्पाद का निर्यात भारत को नहीं किया था, के लिए पाटन की अलग-अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा की जाएगी, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाए कि वे निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिनके उत्पाद के बारे में पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है, से संबंधित नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार समीक्षा की अवधि के दौरान इस अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसे निर्यातकों तथा उत्पादकों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी, जैसा कि उपधारा (1) में उल्लेख किया गया है;

(ग) बशर्ते केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन कर सकती है और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी सिफारिश करते हैं तो आयातक से गारंटी मांग सकती है और यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पाद अथवा निर्यातकों के लिए पाटन का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसे मामलों में समीक्षा की शुरुआत की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगा सकती है।

37. नियम 22 में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है, जिनके अंतर्गत अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना हेतु न्यू शिपर समीक्षा की जा सकती है। निर्यातक देश के किसी भी निर्यात अथवा आयातक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित की जा सकती है, बशर्ते निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति की जाए :-

- (क) कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जांच अवधि के दौरान न किया हो, और
- (ख) कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिनके सम्बद्ध उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया हो, से संबंधित नहीं है।

38. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह पाया है कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने मूल जांच में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि वह निर्यातक देश के किसी भी निर्यातकों अथवा उत्पादकों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, से संबंधित नहीं है। आवेदकों ने प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया है कि उनकी कोई सम्बद्ध/संबंधित कम्पनियां संबंधित उत्पाद के उत्पादन अथवा बिक्री में संलग्न नहीं है। तथापि मौके पर सत्यापन के दौरान संबंधित कम्पनियों के बारे में पूछे जाने पर यह स्पष्ट किया गया था कि प्रवर्तक कम्पनी की अनेक सम्बद्ध कम्पनियां हैं, जो सीएफएल के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कच्चे माल का उत्पादन करती हैं। जहाँ तक इस मुद्दे का प्रश्न है कि क्या इन सम्बद्ध कम्पनियों में से किसी ने संबंधित उत्पाद का निर्यात भारत को किया था, यह दावा किया गया और स्पष्ट किया गया कि चीन जन.गण. की किसी भी सम्बद्ध कम्पनी ने मूल जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत को नहीं किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यू शिपर आवेदक के दावे के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है और इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

39. जांच के दौरान प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के निर्यातकों एवं उत्पादकों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, से संबंध होने का कोई साक्ष्य नहीं पाया और न ही किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यू शिपर जांच समीक्षा की शुरुआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई जो डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप है।

40. नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने की आधारभूत अपेक्षा यह है कि (क) सम्बद्ध वस्तुओं अथवा उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया हो, और (ख) अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध करने वाले निर्यातकों अथवा उत्पादकों द्वारा भारत को सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात जांच अवधि के दौरान न किया गया हो और वे यह दर्शाएं कि वे निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिनके उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, से सम्बद्ध नहीं हैं। समीक्षा हेतु अनुरोध करने वाला न्यू शिपर आवेदक अपने आवेदन में यह घोषणा करने के अलावा, कि वह नियम 22 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने जांच अवधि के दौरान वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था अथवा यह कि वह निर्यातक देश के निर्यातकों, जिनकी सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, से संबंधित नहीं है। यद्यपि प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से पूर्व विस्तृत जांच करना अपेक्षित नहीं है। परंतु यदि आवेदन में दिए गए विवरण के विरुद्ध कोई वास्तविक साक्ष्य है तो प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा शुरू करना अस्वीकार कर सकते हैं। वर्तमान मामले में न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत की तारीख को ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड में दर्ज नहीं था, जो यह दर्शाता हो कि मैसर्स ओसराम चाईना लाइटिंग लि0, चीन जन.गण. (उत्पादक तथा निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत विवरण सही नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं थे और न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत विधि सम्मत हैं।

41. घरेलू उद्योग ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि निर्यातक ने महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय रखा है और विरोधी हितबद्ध पक्षों को इस सूचना को चुनौती देने के अधिकार तथा प्राधिकारी के समक्ष सार्थक निवेदन प्रस्तुत करने से वंचित कर दिया है। तथापि जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्ष को सूचना उपलब्ध कराने का प्रश्न है, प्राधिकारी ने ऐसा गोपनीय के प्रावधानों के अनुसार किया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जो उसमें निर्धारित शर्त के अधीन है। कतिपय सूचना जो व्यावसायिक औचित्य की सूचना है अथवा कोई अन्य सूचना जिसका स्वरूप गोपनीय है (उदाहरणार्थ यदि इसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धी को उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता हो अथवा इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त की गई है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो) अथवा जो जांच के दौरान पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की जाती है, उसे उचित कारण बताए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा। ऐसी सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। इस समीक्षा में व्यवसाय की दृष्टि से संवेदनशील कुछ सूचना गोपनीय रखी गई है जिसमें मुख्य रूप से निगमित संरचना से संबंधित सूचना, विपणन एवं बिक्री व्यवस्थाओं, लेखांकन एवं वित्तीय पद्धतियों से संबंधित सूचना तथा अन्य संवेदनशील सूचना शामिल है, जिसे प्रकट करने से किसी प्रतिस्पर्धी को उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता और कम्पनी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय सारांश एक सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया था, जिसे सभी हितबद्ध पक्षों को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया गया था और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसरण में उनके अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराया गया था।

**घ. पाटन मार्जिन की गणना की विधि**  
**विभिन्न हितबद्ध पक्षों के विचार**

42. मैसर्स इण्डो-एशियन फ्यूज गियर्स लिमिटेड (ख) मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लि० तथा (ग) मैसर्स हेवल्स इण्डिया लि० के विचारों का सारांश निम्नानुसार है।

**बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे के दावे से संबंधित मुद्दा**

43. ओसराम चाईना 3 पणधारकों अर्थात् ओसराम जर्मनी, चीन की एक कम्पनी एफईएलसीई तथा एक हांगकांग आधारित कम्पनी द्वारा शुरू की गई थी। तत्पश्चात् चीन की कम्पनी ने अपने शेयरों का हस्तांतरण ओसराम, जर्मनी को कर दिया। शेयरों के हस्तांतरण के समय पालन की गई शर्तों तथा मूल्यांकन का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

44. आज की तारीख तक यह दावा किया जाता है कि ओसराम, चाईना ओसराम जीएमएचएच तथा मैसर्स प्रोस्पेरिटी लैम्प्स एण्ड कम्पोनेंट्स (हांगकांग) लिमिटेड द्वारा धारित है। यह ज्ञात नहीं है कि ओसराम जीएमबीएच अथवा हांगकांग आधारित अन्य कम्पनी का स्वामित्व किसके पास है। यदि सरकार द्वारा हस्तक्षेप की बात छोड़ दी जाए तो यह सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी है कि क्या इन दोनों कम्पनियों के शेयरहोल्डर चीन के नागरिक हैं। अतः न्यू शिपरों को निर्देश दिया जाए कि वे न्यू शिपर की निगमित सत्ताओं के शेयर होल्डरों का ब्यौरा प्रस्तुत करें और उनके दर्जे की जांच प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

45. न्यू शिपर ने बताया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की खरीदी की है। किसी पाटनरोधी जांच में, जहाँ निविष्टियों की संबंधित सत्ताओं से खरीदी की जाती है वहाँ प्रासंगिक संबंधित सत्ता से उन निविष्टियों के उत्पादन की लागत देते हुए विस्तृत प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करना अपेक्षित होता है। इस मामले में, संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा निविष्टियों के उत्पादन की लागत के संबंध में कोई ब्यौरा दायर नहीं किया गया है। प्राधिकारी न्यू शिपर को संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादन की लागत को दर्शाते हुए ब्यौरेवार प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने का निर्देश दे सकते हैं।

46. इसके अलावा, यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या ऐसे संबंधित आपूर्तिकर्ता चीन अथवा किसी अन्य देश में अवस्थित है। यदि ऐसे आपूर्तिकर्ता चीन अथवा अन्य किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में है तब उनकी उत्पादन की लागत को आगे की जांच अर्थात् कि क्या लागत और हस्तांतरण कीमतें बाजार मूल्य को प्रतिबिम्बित करती है अथवा नहीं, के अध्ययन होना होगा और इसकी विस्तार से जांच की जाएगी।

47. वह प्रारंभिक आधार जिस पर एम ई एस के दावे आधारित है यह है कि उन्हें इसी प्रकार के उत्पाद से संबंधित जांच में ई सी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देशों के अंतर्गत प्रचालित माना गया है। इसी प्रकार की दलील रूस, यूक्रेन और कोरिया जन गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित इंडक्शन हार्डनेड फोर्ज्ड स्टील रोलर्स के लिए दी गई है। उस मामले में निर्यातकों ने माननीय सेसटेट के समक्ष तर्क दिया था कि अमेरिका ने रूस को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है और इसलिए उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय सेसटेट ने माना कि निर्यातक को भारतीय नियमों के तहत यथा अपेक्षित सूचना और साक्ष्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान करना चाहिए और प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दर्जा प्रदान करने से पूर्व नियमों के तहत साक्ष्यों की यथा अपेक्षित जांच करेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार केवल मांग पर नहीं दिया जाएगा।

48. वर्तमान जांच एन एम ई पर संशोधित नियमों के अनुसार की जानी अपेक्षित है और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध। के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार के अपने दावे के संबंध में प्राधिकारी को संतुष्ट करना चाहिए। निर्यातक का अगोपनीय रूपांतर, निर्यातक द्वारा दायर की गई सूचना के सार को समझने के लिए मोटे तौर पर अपर्याप्त और अपूर्ण है। अधिसूचना सं० 28/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) के नोट में चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में रखा गया है।

#### निर्यातक/उत्पादक (न्यू शिपर) के विचार

49. निर्यातक और उत्पादक (न्यू शिपर) के विचारों का सारांश निम्नानुसार है:

50. न्यू शिपर ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार का दावा किया है और इसकी पुष्टि में साक्ष्य दिया है।

(i) चीन जन गण के जनवादी गणराज्य के दिवालियापन कानून में फर्मों के प्रचालन के लिए उपयुक्त विधिक और विनियामक कार्यवाही है और फर्मों को संबंधित कानूनों और विनियमनों के अनुसार मुक्त रूप से दिवालिया घोषित किया जा सकता है ।

(ii) सी एफ एल के विनिर्माण हेतु अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री चीन जन गण में उपलब्ध है । कंपनी मांग और पूर्ति द्वारा तय की गई बाजार कीमतों पर आधारित खुले बाजार से कच्चा माल और अन्य संबंधित निविष्टियां खरीदने के लिए मुक्त है । कच्ची सामग्री अथवा अंतिम रूप से तैयार उत्पाद की कीमतों अथवा लागतों को निर्धारित करने में राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारियों का कोई हाथ नहीं है । प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आयात पर सीधे अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रतिबंध अथवा शर्तें नहीं हैं किन्तु कंपनी ने विदेश से किसी कच्ची सामग्री का आयात नहीं किया है ।

(iii) सुविधाओं पर बिना किसी विशेष अथवा सब्सिडीयुक्त दरों के सामान्य दरें प्रभारित की जाती हैं । विद्युत की आपूर्ति राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा की जाती है तथापि पानी की आपूर्ति निजी कंपनी द्वारा की जाती है । पानी और बिजली पर खपत के ढंग के अनुसार प्रभार लिया जाता है और संबंधित आपूर्ति कंपनियों द्वारा प्रचलित कीमतें प्रभारित की जाती हैं ।

(iv) श्रम के संबंध में, फर्मों को अपने श्रमिकों को संगठित करने और पारिश्रमिक देने की स्वतंत्रता है । शर्त केवल यह है कि फर्म को यह सुनिश्चित करना होता है कि न्यूनतम मजदूरी स्तर की गारंटी हो । कंपनी कारखाने के कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराती है ।

(v) चीन के लेखा संबंधी सिद्धांतों के अनुसार, फर्म को मूल लेखा रिकार्ड कायम रखना होता है और फर्मों को स्वतंत्र लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा अपने लेखा रिकार्डों की लेखा परीक्षा करानी होती है । आवेदकों की लेखा संबंधी पद्धतियां चीन के सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार हैं ।

(vi) भूमि, भवन और मशीनों को उत्पादन और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । ये सुविधाएं कंपनी के स्वामित्व में हैं । चीनी कानून संपदा स्वामित्व का संरक्षण करता है । प्रकृत और विधिक व्यक्तियों को अपनी संपत्ति को रखने, उपयोग करने, उनसे लाभ कमाने और उन्हें बेचने का कानूनी अधिकार है । चीन के जनवादी गणराज्य के नागरिक कानून के सामान्य सिद्धांतों में यह निर्धारित है कि किसी स्वामी को अपनी संपत्ति को रखने, उपयोग करने, उनसे लाभ कमाने और उन्हें बेचने का कानूनी अधिकार है । अतः फर्म दिवालियापन और संपदा कानूनों, दोनों के अधधीन हैं जो व्यापार के प्रचालनों के लिए कानूनी स्थायित्व और सुनिश्चितता की गारंटी देती है ।

(vii) कंपनी विनियम-व्यापार अथवा पटल व्यापार में कभी भी अंतर्ग्रस्त नहीं रही है । कंपनी कभी भी मुआवजा व्यापार (जो उत्पाद की वापसी खरीद के नाम से भी जाना जाता है) में अंतर्ग्रस्त नहीं रही है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के आकलन के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार इस पूर्वानुमान से कार्यवाही की कि किसी भी देश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा जांच से पहले की 3 वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। पिछले तीन वर्षों में चीन जन गण को ई यू तथा संयुक्त राज्य अमरीका जैसे डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा अपनी पाटनरोधी जांचों में चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। मौजूदा मामले में चीन जन गण की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में जांच किए जाने का प्रस्ताव है।

52. प्राधिकारी ने मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कं0 लि0, चीन जन गण. (निर्यातक) को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली भेजी। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार के अपने दावे के समर्थन में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की खरीद के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुरोध किया है। एम ई टी व्यवहार के अपने दावे के मद्देनजर, प्रत्युत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक के परिसर में सत्यापन किया गया था। चीनी उत्पादक ने इस आधार पर वैयक्तिक व्यवहार का दावा किया है कि वे अपनी व्यापारिक गतिविधि में बिना किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष राज्य हस्तक्षेप अथवा प्रभाव के देश में प्रचलित अर्थव्यवस्था की स्थिति से निरपेक्ष बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दशाओं के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।

53. पाटनरोधी जांच में चीन जन गण के मूल के आयातों से संबंधित सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा।

54. आगे पाटनरोधी नियमावली (यथासंशोधित) के अनुबंध 1 के पैरा 8 में प्रावधान है कि:

(1) 8(1) "गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" शब्द का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती हैं।

(2) यह परिकल्पना की जाएगी कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

(3) तथापि, गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करती हो कि ऐसा देश उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

55. यह नोट किया जाता है कि प्रत्युत्तरदाता चीनी उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित कसौटी पर विचार करने में समर्थ बनाने के लिए पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) में यथा उल्लिखित सूचना/साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्य को दर्शाती हैं;

(ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती हैं, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के ह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; तथा

(ग) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं;

(घ) तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

56. आवेदक से विस्तृत प्रश्न जो स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, वाणिज्यिक और व्यापारिक नीतियों और वित्तीय स्थिति का निर्धारण आदि से संबंधित थे, किए गए थे। न्यू शिपर द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तरों का यह निर्धारित करने के लिए विश्लेषण किया गया कि क्या आवेदक ने चीनी सरकार से स्वतंत्रता के किसी स्तर का उपयोग किया जो कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित नहीं होती। प्राधिकारी ने आवेदक से निम्नलिखित मापदण्डों के संबंध में सामान्य और कतिपय विशिष्ट सूचना चाही:



- स्वामित्व संबंधी व्यौरे
- अंशधारिता के तरीके
- प्रवर्तक/धारक कंपनी/कम्पनियों संबंधी सूचना
- निदेशक मंडल के घटक, उनकी विधिक प्रस्थिति और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति/पक्षकार
- कच्ची सामग्री, निविष्टि और लागतें
- राज्य द्वारा निर्धारित किसी न्यूनतम मजदूरी की विद्यमानता अथवा अन्यथा और क्या उद्यम बाजार की मांग के अनुसार मजदूरी का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है।
- उत्पादन सुविधा और लागतें
- ऋण और सब्सिडी
- विनिमय व्यापार/पटल व्यापार
- लाभ वितरण
- दिवालियापन तथा संपत्ति कानून
- मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन

57. संसाधनों के आबंटन तथा आवेदक के दावों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के किसी भी तरह के प्रभाव अथवा हस्तक्षेप का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता के स्वामित्व पैटर्न की जांच की गई। हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए दावों/प्रतिदावों पर विचार किया गया और इस संबंध में विवरणों का सत्यापन किया गया। व्यवसाय लाइसेंस के अनुसार कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाला विदेशी उद्यम है जिसमें शेयरों का बहुत बड़ा प्रतिशत मै0 ओसराम जी एम बी एच तथा एक छोटा हिस्सा मै0 प्रॉस्पैरिटी लैम्स एंड कंपोनेंट्स (एच के) लि0 के पास है। मूल रूप से मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग लि0 पर तीन शेयरधारकों का स्वामित्व था जिनमें अधिकांश शेयर मै0 ओसराम जी एम बी एच के पास थे, हालांकि इसके बाद ओसराम जी एम बी एच ने अन्य कंपनी के शेयर खरीद कर स्थिति सुदृढ़ कर ली। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य विदेशी नागरिक हैं। प्राधिकारी ने कंपनी के निदेशक मंडल के संघटन, उनके कार्यों की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कंपनियों के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप या भागीदारी है। प्राधिकारी निदेशक मंडल, पर्यवेक्षण मंडल, महाप्रबंधक की नियुक्ति, उनके कार्यों तथा अधिकारों, नियुक्ति तथा निष्कासन, नियुक्ति आदि के मामलों में कंपनी की स्वायत्तता और ऐसी कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अथवा राज्य के निजी/उसके द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों/निकायों की भूमिका, यदि कोई हो, के संबंध में संगत प्रावधानों पर निर्भर रहे।

58. यह पाया गया है कि कच्चा माल खुले बाजार से और बाजार मूल्यों पर खरीदा गया क्योंकि विभिन्न कच्चे माल की कीमतों में अंतर था और उन्हें बाजार कीमतों पर क्रय किया गया था। यह पाया गया था कि कंपनी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल चीन जन गण में एक सहयोगी/संबंधित कंपनी से लेती है। जांच अवधि के दौरान संबंधित पक्ष ने किसी अन्य स्वतंत्र क्रेता को उक्त कच्चा माल

नहीं बेचा है। उसके अनुसार निर्यातक को सहयोगी कंपनी से उक्त कच्चे माल की उत्पादन लागत के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए कहा गया था जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि हस्तांतरण कीमत उचित कीमत को दर्शाती है। निर्यातक द्वारा उसकी प्रतियाँ सत्यापन के बाद प्रस्तुत की गई। यह देखा गया है कि संबंधित पक्ष द्वारा प्रभारित कीमत, लागत तथा तर्कसंगत लाभ के जोड़ पर आधारित है। इसे ही प्रतिनिधि माना गया है।

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी से बिजली खरीद रही है। चूँकि बिजली राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त की गई इसलिए प्राधिकारी ने उस टैरिफ की जाँच की जिस पर कंपनी को बिजली दी जा रही थी। बीजकों की प्रतियाँ ली गईं और कंपनी द्वारा दिए गए टैरिफ का पता लगाया गया। यह पाया गया कि बिजली खपत के पैटर्न और संबंधित बिजली/जल आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रभारित वर्तमान कीमतों के अनुरूप प्रभारित की गई है।

60. यह पाया गया कि कंपनी चीन के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अपने लेखा रख रही है। कंपनी मासिक रूप से लाभ एवं हानि विवरण तैयार करती है जिसमें वैट के साथ लाभ एवं हानि का विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है। जाँच अवधि के प्रत्येक माह के लाभ एवं हानि विवरण की जाँच की गई और कंपनी द्वारा वैट विवरणों के साथ फाइल किए गए लाभ एवं हानि विवरण के साथ उसका फिर से सत्यापन किया गया तथा संबद्ध वस्तु तथा अन्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग लाभप्रदता पाई गई। कंपनी के लेखा की लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा होती है और कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखापद्धतियों के संबंध में उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं पाई गई।

61. दिवालियापन तथा संपत्ति कानूनों की जाँच की गई और पाया गया कि कंपनी संपत्ति लेने के लिए स्वतंत्र है। दिवालियापन कानून किसी फर्म पर तब लागू होता है जब फर्म दिवालिया हो जाती है और देयताओं के भुगतान से संबंधित ब्यौरे दिवालियापन कानून के तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

62. उनकी लेखा बहियों से मुद्रा विनिमय परिवर्तनों की भी जाँच की गई और यह पाया गया कि निर्यात के प्रेषित धन को सौदे की तारीख पर वर्तमान मुद्रा विनिमय दर के अनुसार चीनी मुद्रा में परिवर्तित किया गया। जाँच दौरे के दौरान यह देखने के लिए निर्यात बीजकों की जाँच की गई कि क्या वसूली गई रकम उनकी लेखा बहियों में जमा की गई है। प्राधिकारी ने यह देखा कि मुद्रा विनिमय परिवर्तन मौजूदा दर पर ही हुए हैं जो लगभग स्थिर थी।

ऊपर उल्लिखित सूचना और सत्यापित तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (क) (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं।

### सामान्य मूल्य

63. धारा 9 क (1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

(i) उपधारा (6) के तहत नियमानुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए अभिप्रेत समान वस्तु हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत; या

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में किसी विशेष बाजार स्थिति अथवा बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री किसी समुचित तुलना की अनुमति नहीं देती, तब सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई होगा:-

(क) उपधारा (6) के तहत नियमानुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र अथवा किसी समुचित तीसरे देश से निर्यातित समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत; या

(ख) उपधारा (6) के तहत नियमानुसार यथानिर्धारित मूल देश में प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागतों हेतु तर्कसंगत परिवर्धन के साथ उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ।

(ग) प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण (निर्यातक) को निर्यातक प्रश्नावली भेजी । प्रश्नावली के उत्तर में न्यू शिपर ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचना दर्ज की । उन्होंने चोक के साथ तीन आकारों के सी एफ एल का निर्यात किया है और उनके घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना दी गई है । धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्यातक देश में खपत के लिए अभिप्रेत समान वस्तु हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री की तुलनीय कीमत है । उन्होंने जाँच अवधि के दौरान उत्पादित और भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आकारों/मॉडलों/प्रकारों की उत्पादन लागत का ब्योरा भी दिया है । कंपनी द्वारा तैयार लेखा-बहियों से अंश-वार उत्पादन लागत की भी जाँच की गई । कंपनी के लाभ तथा हानि विवरण के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि कंपनी ने जाँच अवधि तथा कैलेंडर वर्ष के दौरान संबद्ध वस्तु की बिक्री पर समग्रतः लाभ कमाया है । एस जी ए समेत उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य तथा चोक सहित सी एफ एल के इन मॉडलों/प्रकारों हेतु तर्कसंगत लाभ को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए समुचित आधार माना गया है ।

64. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कंपनी ने जाँच अवधि के दौरान भारत को दो आकार के सी एफ एल के विभिन्न मॉडलों/प्रकारों का निर्यात किया है । ये मॉडल चोक सहित सी एफ एल के प्रकार हैं । उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर चोक सहित सी एफ एल के इन मॉडलों/प्रकारों हेतु आकार वार/मॉडल/प्रकार वार कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नांकित है:

क्र.सं.	सी एफ एल का आकार/मॉडल/प्रकार	सामान्य मूल्य (अम.डा. प्रति नग)
1	सी 8 वॉट्स	***
2	सी 11 वॉट्स	***
3	सी 14 वॉट्स	***

### सी.एफ.एल.

दिल्ली के उत्तर में निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का एक-वार प्रत्येक-वार ब्यौरा अनुबंध - 2 में प्रस्तुत किया है। उसके समर्थन में निर्यातक ने कंपनी की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। भारत को निर्यात एफ ओ बी आधार पर मै0 ओसराम इंडिया लि0 को विपणित किया है जो एक संबंधित कंपनी है। निर्यातक ने एफ ओ बी स्तर तक खर्चों के समायोजन में ध्यान दिया है। कंपनी ने अपने एक सहयोगी मै0 ओसराम इंडिया लि0 को विक्री की है। एफ ओ बी के खर्च उक्त आयातक द्वारा उठाए गए हैं। एफ ओ बी से ब्यौरे प्राप्त करने के लिए मांगे गए थे। अवतरण, परिवहन, बीमा, दिए गए सीमाशुल्क आदि के संबंध में आयातक के दावों के अनुसार समायोजन सत्यापित आंकड़ों पर आधारित माना गया है और भारत में निर्यात कीमत निकालने के लिए इसकी अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मै0 ओसराम इंडिया लि0 द्वारा तैयार भारतीय ग्राहकों से संबंधित बीजकों की जाँच की गई है। उनके द्वारा किए गए दावों के साथ उनका निपटारा किया गया। जाँच के दौरान दिल्ली में निर्यातक के पास हुए रिकॉर्ड से समायोजन के उनके दावों से संबंधित ब्यौरों की जाँच की गई। समायोजन के संबंध में सत्यापित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। संबद्ध वस्तु की आकार-वार तथा मॉडल/प्रकार-वार कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण है।

क्र.सं.	आकार/मॉडल/प्रकार	निर्यात कीमत (अम.डा. प्रति नग)
1	सी 8 वॉट्स	***
2	सी 11 वॉट्स	***
3	सी 14 वॉट्स	***

निर्यात कीमत का निर्धारण हेतु ऊपर उल्लिखित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों को एक-वार प्रत्येक-वार मार्जिन के निर्धारण के बाद कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लेम्प्स (सी एफ एल) के लिए किया गया है। यह निर्धारण किया गया है कि निर्यातक ने संबद्ध वस्तु का

निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया है और प्रति सी एफ एल भारत औसत पाटन मार्जिन 0.16 अम.डा. निर्धारित किया गया है ।

### प्राधिकारी की सिफारिशें

67. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि

(i) मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कं0लि0, चीन जन गण द्वारा उत्पादित तथा भारत को निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सी एफ एल) की निर्यात कीमत जाँच अवधि के दौरान सामान्य मूल्य से कम है ।

(ii) अतः प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के तहत आने वाले तथा मै0 ओसराम चाइना लाइटिंग कं0 लिमिटेड, चीन जन गण द्वारा उत्पादित तथा भारत को निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सी एफ एल) के निर्यातों पर प्रति सी एफ एल 0.16 अम.डा. के पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं ।

68. अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2007

**Final Findings**  
**(New Shipper Review)**

**Subject : New Shipper Review (under Rule 22 of AD Rules) of anti-dumping duty imposed on imports of Compact Fluorescent Lamps (CFL) requested by M/s. Osram China Lighting Ltd., China PR.**

**F. No. 15/27/2004-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof,

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed:
  - (i) The Designated Authority received a request from M/s. Osram China Lighting Limited, China(hereinafter referred to as New shipper) to initiate under Rule 22 of above mentioned Rules a review of notification No 34/1/2001 dated 14<sup>th</sup> November, 2002 for determination of individual dumping margin. The applicant submitted declarations that they are not related to any of the exporters and producers in China PR subject to the anti dumping measures in force with regard to the product concerned. Furthermore, they declared that they have not exported the product concerned during the period of investigation of the original investigation. The Authority examined the information submitted by the applicants and considered prima-facie sufficient to justify the initiation of a review in accordance with the provisions of the Rule 22 of Anti-dumping Rules.
  - (ii) The Authority initiated the New Shipper Review on the basis of request made by M/s. Osram China Lighting Limited ,China

(producer and exporter) under Rule 22 of AD Rules, vide notification No. 15/27/2004-DGAD, dated 15<sup>th</sup> February, 2005

- (iii) The aforesaid New Shipper Review was initiated in the matter of import of Compact Fluorescent Lamps(CFL) falling under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR where the Designated Authority vide its Final Findings No 34/1/2001 dated 14<sup>th</sup> November, 2002 had come to the conclusion that:
- (a) CFL originating in and exported from the People's Republic of China and Hong Kong have been exported to India below normal value resulting in dumping,
  - (b) The Indian industry has suffered material injury from exports of CFL from People's Republic of China and Hong Kong ;
  - (c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports from the People's Republic of China and Hong Kong,
  - (d) In case of exports of CFL with choke by M/s Phillips & Yaming. PRC , causal link could not be established as the landed value of such exports was more than the Non-Injurious Price .
- (iv) The Central Government imposed anti-dumping duty vide Notification No. 138/2002-Customs, dated 10.12.2002, in the original investigation on imports of Compact Fluorescent Lamps from China PR and Hong Kong falling under Chapter 85 of Customs Tariff Act, with effect from the date of imposition of the provisional anti dumping duty i.e., 2<sup>nd</sup> November, 2001;
- (v) The Authority recommended provisional assessment of all exports of Compact Fluorescent Lamps made by M/s. Osram China Lighting Co. Limited ;China P.R. (producer and exporter) till the completion of the New Shipper review in accordance with Rule 22 of AD Rules and having regard to the Notification no.138/20032-Cus dated 10.12.2002;
- (vi) Ministry of Finance issued Notification No. 7/2006-Customs, dated 13<sup>th</sup> February, 2006, which inter-alia provided that pending the outcome of the review by the Designated Authority, exports of Compact Fluorescent Lamps, falling under Sub-heading 853931 of the first scheduled of the said Customs Tariff Act. by M/s. Osram China Lighting Co. Limited ,People's Republic of China, when imported into India would be subjected to provisional assessment till the review was completed. It was further provided that the provisional assessment may be subject to security or guarantee as the assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, deems fit for payment of deficiency, if any, in case a definitive anti dumping duty is imposed retrospectively, on completion of the investigation by the Designated Authority. In case of recommendation of Anti-Dumping Duty after completion of the said review by the Designated Authority

, the importer shall be liable to pay the amount of such duty recommended on review and imposed on all imports of Compact Fluorescent Lamps into India, exported by M/s Osram China Lighting Co. Limited, People's Republic of China, when imported into India, from the date of initiation of the said review.

- (vii) The product under consideration covered by the current review is the same as in the original investigation, i.e. 'Compact Fluorescent Lamps'.
- (viii) The Authority sent a copy of exporter's questionnaire and Market Economy Treatment (MET) questionnaire to M/s. Osram China Lighting Co. Limited, China P.R. (producer and exporter). The authority sought information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping margin. The Authority conducted verification of the data furnished by M/s. Osram China Lighting Co. Limited, (producer and exporter) at their premises.
- (ix) The authority sought information from M/s Osram India, an importer, with regard to imports, related expenses and sales to first independent buyer. Information provided by the importer was verified at their premises.
- (x) The period of investigation in this new shipper investigation is for 6 months i.e., 1<sup>st</sup> January, 2005 to 30<sup>th</sup> June, 2005 for dumping determination.
- (xi) The authority officially intimated the authority of the exporting country of the initiation of the New Shipper Review and gave opportunity to all the interested parties concerned to make their views known in writing within 40 days from the expiry of the POI (i.e. 1<sup>st</sup> January, 2005 to 30<sup>th</sup> June, 2005).
- (xii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 02.02.2006. All parties presenting their views orally were requested to file written submissions of the views expressed verbally.
- (xiii) The Authority made available the public file as per Rule 6(7) to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
- (xiv) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received thereon have also been duly considered in the findings.
- (xv) \*\*\*\* in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules. The information concerning prices and



costing filed by the applicant were claimed confidential and these were treated as confidential by the Authority;

**B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

2. The Authority decided to continue with the description of product under consideration as Compact Fluorescent Lamps as determined in the original case. Certain issues with regard to product under consideration and like article have been raised by some of the interested parties.

**Views of M/s. Indo-Asian Fuse Gear Ltd, (b) M/s. Phillips India Ltd and (c) M/s. Havells India Ltd.**

3. It has been submitted that

- (a) Neither the application nor the written submissions filed on behalf of the new shipper state that the scope of the new shipper review is restricted to certain types of CFLs only and not to all types of CFLs. It is undisputed that the types of CFL that Osram India is intending to import into India are direct substitutes of the types of CFLs that are being manufactured and sold in India. Further, the other domestic producers have the capability to produce these twisted and miniaturized CFLs, though they have not so far manufactured them. The imports of those types of CFLs into India would severely and adversely affect the Indian market for CFLs. This is because these new generation CFLs would cut into the market of the existing CFLs.
- (b) During the hearing the counsel for the new shippers stated emphatically that the scope of the review is limited to miniaturized and twisted CFLs [T3 lamps].
- (c) However, no such declaration has been given in the written submissions. The new shippers may be directed to categorically state whether they seek the new shipper review for all types of CFL or it is restricted to only certain types of CFLs. If it is restricted to certain types of CFLs, the name, description and complete specifications of those types of CFLs may be furnished immediately.
- (d) The petitioners in their request letter dated 22.11.2004, has stated that they manufacture miniaturised and twisted CFL at Osram, China, and they intend to export these miniaturised and twisted CFL from China to India. It is not known whether Osram China is also engaged in the manufacture of CFLs other than miniaturised and twisted CFLs. It is also not known whether the new shippers are desirous of covering all types of CFLs or they seek new shipper review only for the restricted category, i.e. miniaturised and twisted CFL.
- (e) From the original investigation records it may be seen that Osram India had imported CFLs from Germany during the period of investigation. It is not known whether these CFLs were manufactured at the factory of Osram China or they were of Germany or any other make. This question needs to be examined in detail.
- (f) It has been stated by the exporter that one of their Chinese related company M/s. Chung Tak Lighting Control Systems (PANOU) Ltd. Osram

China produces different types of CFL and names them as CFL I, CFL II, CFL III, etc. It is not known whether the related company is engaged in the manufacture of other types of CFLs i.e. CFL-OII, CFL-III etc. It must be noted that the investigation covers each and every type of the product concerned. There cannot be any exception or exclusion from the scope of the product concerned, by describing the product as CFL-I, CFL-II etc. The authority needs to examine whether the exporter had imported the product concerned to India during the investigation period irrespective of whether the said product is categorised as CFL-I or not.

#### **Views of the New Shipper**

4. The OSRAM group through its Indian operations continues to make investments in the CFL business in India. As stated earlier, as per group policy goods from OSRAM company in one country is exported to other countries. M/s Osram India Ltd. exports several products, including lamps to other countries.

M/s OSRAM India Ltd. does not intend to import and the Applicant will not export any CFL made by its group company to India.

#### **Examination by the Authority**

5. The product under consideration in the original investigation was Compact Fluorescent Lamps (CFL) with or without choke or ballast, with one or more glass tubes and which have all lighting elements, all electronic components and cap integrated in the lamp foot, originating in or exported from China PR. The product is classified under custom tariff heading 8539.31. The classification is, however, indicative and in no way binding on the investigation. The present investigation is only New Shipper Review (NSR) under Rule 22 of AD Rules for determination of individual dumping margin for the applicant M/s Osram China Lighting Ltd., China PR, therefore, the description of product under consideration for the purpose of this investigation is same as in original investigation as manufactured and exported by M/s Osram China Lighting Ltd.

### **C. VIEWS EXPRESSED AT/AFTER INITIATION AND THEIR EXAMINATION**

#### **Views of various interested parties**

6. Views of M/s. Indo-Asian Fuse Gear Ltd, (b) M/s. Phillips India Ltd and (c) M/s. Haveils India Ltd. have been summarised below:

#### **NSR Application is malafide and hence the investigation is liable to be terminated without any further action**

7. M/s Osram India, as a domestic producer, filed a petition along with Indo-Asian and got the existing measures imposed. Now M/s Osram India is seeking a new shipper review for its related company. This indicates pre-planned attempt on the part of Osram India to restrict import of CFLs from all manufacturers from China and subsequently they are trying to exclude their

related company, leading to a situation where Osram China has a distinct competitive edge over other producers from China.

8. The entire exercise appears to be malafide. Therefore, the authority shall not continue the investigation and terminate the same without any further action.

**Initiation is faulty**

9. The Designated Authority has relied upon one line statement for initiating the NSR. The exporter has to provide evidence before the Authority to show that he has not exported the goods to India during the relevant year. The Application did not contain any evidence in support of the claim that the applicant has not exported the product to India during the relevant period.

10. The exporter is required to show that they are not related to any other producer or exporter in the exporting country who are subject to Anti Dumping Duties. The new shipper did not produce any evidence to show that they are not related to any producer or exporter of the product concerned during the relevant period. Therefore the initiation is faulty.

**New Shipper Review is not the appropriate proceeding in the facts and circumstances of this case**

11. In terms of Rule 22, the scope of a NSR is restricted to determination of dumping margin for the new shipper. No issues relating to injury, status of domestic industry, etc need to be examined.

12. However, when a domestic producer after getting the anti-dumping measures imposed, starts causing injury to itself by importing the product into India, the authority has to examine whether there is a justification to continue the duty at all. The authority cannot simply conduct a new shipper review under Rule 22 that is restricted to dumping aspects only.

13. In terms of Rule 2(b), when domestic producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves the importers thereof, such producers may be deemed not to form part of the domestic industry. Once a domestic producer or its related exporter seeks a new shipper review and starts importing the subject goods from the subject country, the question of whether the said producer shall be deemed to be a part of the domestic industry or not, assumes greater significance. If the authority decides that the said producer shall not form part of the domestic industry, then the existing measures needs to be reviewed for determining the correct degree and extent of injury suffered by other domestic producers.

14. This is a fit case for reviewing whether there is a need to continue or withdraw the existing measures after considering both dumping and injury. However, the scope of a new shipper review investigation is restricted to dumping aspects only. Therefore, new shipper review is not an appropriate proceeding in the facts and circumstances of the case. It needs to be terminated immediately without any further action.

### **STATUS OF OSRAM INDIA NEEDS TO BE DETERMINED IN THIS CASE**

15. In written submissions, Osram India has given a long list of 10 factors that are required to be considered by the authority regarding the status of Osram India as a constituent of the domestic industry. Osram India has not given any information with regard to the 10 factors listed out by them. Without giving any information whatsoever, listing out the factors alone, would serve no purpose. Further, if the authority has to consider the status of Osram India as a constituent of domestic industry, these 10 factors alone are not sufficient. The authority may require substantive information in respect of a number of other factors.

16. An examination is unavoidable in this case, but under Rule 22 Designated Authority does not have the powers to conduct an examination of such issues in a new shipper review.

17. If the authority decides to continue with the new shipper review, it is necessary to obtain full details about all the relevant factors about the status of Osram India. Without such a detailed examination, an unbiased and objective decision cannot be arrived at in this new shipper review.

### **REASONS FOR CLAIMS OF CONFIDENTIALITY NOT PROVIDED**

18. The new shipper has claimed confidentiality to a significant portion of the information submitted in the exporters' questionnaire response. The new shipper is under obligation to provide information which shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. This is an important element incorporated in Rule 7 (2) which reflects the balance struck by the rules between the need to protect the confidentiality of certain information, on the one hand, and the need to ensure that all parties have a full opportunity to defend their interests. It is submitted that the information provided by the New Shipper is inadequate to appropriately respond in the matter.

19. The questionnaire response filed by the present applicants does not give any reason whatsoever. Therefore, the questionnaire response filed by the new shippers may be rejected or the new shippers may be directed to file a revised non-confidential version of the questionnaire response giving reasons as to why confidentiality is required in respect of every item/data/information for which they have claimed confidentiality.

### **EXPORTERS QUESTIONNAIRE RESPONSE IS HIGHLY INADEQUATE**

20. The questionnaire response filed by the new shipper is highly inadequate. The NME questionnaire response is in the old format. It shall be given in the new format. The new shipper does not seem to have filed the Memorandum and Articles of Association of the company alongwith the NME questionnaire.

21. The response to the main questionnaire is highly incomplete. Number of deficiencies have been pointed out. The information furnished in the response is not consistent between various part of the questionnaire. In view of the number of deficiencies pointed out the accounting system as well as record keeping system of the exporter does not appear to be reliable.

### **EXPORT PRICE IS NOT RELIABLE**

22. Export price to India is not reliable on account of (a) it is to a related party in India; and (b) export price to third countries are significantly lower than the export price to India.

23. It appears that Osram China has indicated an unreasonably high export price that does not reflect the market reality for the purposes of getting a favourable result in this new shipper review. Further, in the original non-confidential version of the questionnaire response submitted on 03.10.2005 they had expressly mentioned that the future orders depend upon the results of the new shipper review. This statement clearly shows that the export price is only for the purposes of this investigation and is not a regular price at which it would be exported in the normal course.

24. Section 9A (1) which states that the export prices shall be constructed in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association between the exporter and the importer. The said explanation further provides that in such cases export price may be constructed on the basis of the price at which imported articles are first resold to an independent buyer. The provisions of explanation B to Section 9A (1) are clearly applicable to the facts of this case and therefore the authority shall construct the export price as required under the rules.

### **OTHER ISSUES**

25. In response to the NME questionnaire, the new shippers have stated that they do not have any loans. However, their accounts show significant financial expenses. If they had taken loans earlier that have been repaid before the completion of the period of investigation, the authority shall obtain the details of such loans and see whether such loans have been obtained under market conditions.

### **VIEWS OF THE NEW SHIPPER**

#### **Proof of non-export of CFL to India during the original period of investigation:**

26. Within the factual matrix of the case at hand, the Applicant in the new shipper review are related to a constituent of the Domestic Industry in the original investigation. In fact they are from the same group. As per group policy and practice exports from one Osram Company are done only to Osram group companies in another country.

27. During the original investigation, it was clearly stated that Osram India had no imports of CFL in the original period of investigation. This was further investigated by the Hon'ble Designated Authority in that investigation and was confirmed.

28. At the outset of this new shipper review, it was categorically stated by the Applicant that the exports will only take place within the OSRAM group. In fact the exports made during the New Shipper Period of Investigation were made to OSRAM India who have duly filed an importers questionnaire which has been verified by the Hon'ble Designated Authority.

29. The Applicant has affirmed that no CFL exports have ever been made to India and the same can be ascertained from the detailed submissions already on record, as well as verified during the verification visit; for which the Applicant reiterates its offer for full and complete cooperation.

30. It is submitted that the interpretation of the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of H.R. Johnson India Ltd. v/s. Designated Authority is erroneous and overly burdensome. Given that the law India's WTO commitments, the provisions of the Customs Tariff Act and past jurisprudence all provide for new shipper reviews. The CESTAT provided guidance on how these provisions must not be abused by those with vested interests. This cannot be interpreted as being so burdensome so as to do away with all New Shipper Reviews. Indeed the Interested Opposing Parties by requiring conclusive evidence that the Applicant's provide conclusive proof that they are related to any exporter/producer during the original period of investigation are propounding an interpretation which is impossible to meet. To further elaborate this, with due respect, even the Hon'ble Designated Authority is unable to identify every exporter in the original investigation, as it may be likely that some did not cooperate or others exported through trading companies or other third parties. Consequently proving the negative as the interested opposing parties are demanding is well near impossible.

31. On the other hand, the Applicant is publicly traded, duly audited enterprise. To meet the requirement by the law the Applicant has disclosed:

- o All its related Companies
- o All its exports
- o Stated under oath that its disclosures are full and complete and
- o Is inviting the Hon'ble Designated Authority to verify all of the above and any other appropriate data.

32. In light of the above, it is respectfully submitted that the standard of proof imposed by the Hon'ble Designated Authority in the facts of this case is appropriate and in accordance with the law.

### **Confidentiality Claims**

33. As per the requirement of the Hon'ble Designated Authority the Application had given reasons for its request for confidential treatment.

Subsequently a detailed letter providing detailed reasons for requesting confidentiality was provided once again and the same is placed on record with the Hon'ble Designated Authority.

### **Inaccuracy of Data and the Incomplete MET Questionnaire**

34. As per the request of the Designated Authority dated 14<sup>th</sup> February, 2006, the Applicant has provided detailed data clarifying several issues, including those raised by the Interested Opposing Parties and the same is on record.

### **Export Price**

35. With reference to the allegation of unreliable export prices, the Hon'ble Designated Authority had considered this issue in the original investigation concerning the same product and the Applicant believes that the same will be an appropriate within the factual matrix of the case.

### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

36. The Designated Authority initiated new shipper review keeping in view the provisions of the anti dumping rules, which are reproduced below:

- (a) *"Rule 22: (1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.*
- (b) *The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:*
- (c) *Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review".*

37. Rule 22 clearly specifies the circumstances under which a new shipper investigation can be carried out for the purpose of calculating individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied;

- (a) that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation and,
- (b) that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product concerned.

38. The Designated Authority in the present case on the basis of information filed by the applicant found that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation in the original investigation and provided certification that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to anti dumping duties. The applicants in their response to the questionnaire claimed that they had no affiliated/related companies engaged in production or sale of the product concerned. However, at the time of spot verification, on being asked regarding related companies, it was clarified that the promoter company has number of related companies engaged in production Raw materials required for manufacture of CFL. With regard to the issue whether any of these affiliates had exported the product concerned to India, it was claimed and clarified that none of the affiliates from China PR had exported the subject goods to India during the original period of investigation. The Authority notes nothing adverse could have been assumed against the claim of the new shipper applicant and no such evidence was found in this regard.

39. During the investigation the Authority neither found any evidence of relationship with any of the exporters and producers in China PR who are subjected to anti-dumping duty nor any material evidence in this regard was brought before the Authority by any interested parties. The Authority, therefore, notes that the New Shipper Review investigation was initiated as per provisions laid down in Rule 22 of the anti-dumping rules which is in conformity with article 9.5 of the WTO AD Agreement.

40. The basic requirements for initiating the New Shipper Review under Rule 22 are that (a) the subject goods or the product must be subjected to anti-dumping duty, and (b) the exporters or producers who are seeking determination of individual margin of dumping must not have exported the subject goods to India during the period of investigation and they must show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. The new shipper applicant who is seeking review, apart from making a declaration in the application that he fulfils the above conditions set out in Rule 22, cannot adduce any evidence that he had not exported the goods during the period investigation or that he is not related to the exporters in the exporting country who are subject to anti-dumping duty on the subject goods. For prima facie satisfaction though Authority is not required to conduct a detailed enquiry before initiating new shipper review, if there is material evidence to contradict the statements made in the application, then the Authority can refuse to initiate the new shipper review. In the present case, on the date of initiation of new shipper review, there was no material on record to show that the statements made by M/s. Osram China Lighting Co.Limited, China PR(Producer and exporter) were not correct. Therefore, it cannot be said that there was no prima facie satisfaction on the part of Authority



before initiating the new shipper review and the initiation of the new shipper review is in order.

41. It is argued by the domestic industry that the exporter has kept the vital information confidential depriving the opposing interested parties of the right to challenge the information and make the meaningful submissions to the Authority. However, regarding the information made available to the opposite interested party the Authority has dealt with it as per provisions regarding confidentiality. Rule 7 of the Anti Dumping Rules provides for submission of information by the interested parties on confidential basis subject to the condition laid down therein. Certain information which are either business proprietary information or any other information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it. In this review certain business sensitive information has been kept as confidential mainly information pertaining to corporate structure, marketing and selling arrangements, accounting and financial practices, and other sensitive information disclosure of which would have been of significant competitive advantage to a competitor and would adversely affect the business of the company. The non-confidential summary of the information submitted on a confidential basis is placed in the public file, which is available for the inspection, by all the interested parties and copies of the same were provided as and when requested in terms of Rule 6 (7) of the Anti Dumping Rules.

#### **D. METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN**

##### **VIEWS OF VARIOUS INTERESTED PARTIES**

42 Views of M/s. Indo-Asian Fuse Gear Ltd, (b) M/s. Phillips India Ltd and (c) M/s. Havells India Ltd. have been summarised below:

##### **Issue relating to Market Economy Status claims**

43. Osram China was started with 3 shareholders namely Osram Germany, FELCE- a Chinese company and a Hong Kong based company. Subsequently, the Chinese company transferred its shares to Osram, Germany. The details of terms and the valuation adopted at the time of transfer of shares have not been furnished at all.

44. As on date, it is claimed that Osram, China is held by Osram GmbH and M/s. Prosperity Lamps & Components (Hong Kong) Limited. It is not known who owns Osram GmbH or the other Hong Kong based company. If the shareholders of any of these 2 companies are Chinese nationals, whether government interference can be ruled out, needs to be carefully examined. The new shippers may be directed to file the details of the shareholders of the

465261/07-5

corporate entities that own the shares in the new shipper and their status may be examined by the authority.

45. The new shipper has stated that they have purchased materials during the period of investigation from related suppliers. In an anti dumping investigation where inputs are procured from related entities the relevant related entity is required to file a detailed questionnaire response giving the cost of production of those inputs. In this case, no details relating to the cost of production of the inputs by the related suppliers have been filed. The authority may direct the new shippers to file detailed questionnaire responses indicating the cost of production of related suppliers.

46. Further, it is also not known whether such related suppliers are located in China or in any other country. If such suppliers are in China or in any other non-market economy country, their cost of production would have to be subjected to further examination i.e. whether the costs and the transfer prices reflect market values or not, is to be examined in detail.

47. The primary ground on which the MES claim stands is that they have been held to be operating under Market Economy Conditions by EC in an investigation relating to the same product. A similar plea was raised in Induction Hardened Forged Steel Rolls originating in or exported from Russia, Ukraine and Korea R.P. In that case, the exporters argued before the Hon'ble CESTAT that USA has declared Russia as a market economy country and therefore they shall be granted market economy treatment. However, the Hon'ble CESTAT did not agree with such a view. The Hon'ble CESTAT held that the exporter should provide the information and evidence to the Designated Authority as required under the Indian rules and the authority shall examine the evidence as required under the rules before granting market economy status. Market economy treatment shall not be granted just for the asking.

48. The present investigation is required to be conducted in accordance with the amended Rules on NME and normal value should be determined as per para 7 of the annex-I of AD Rules. The exporter must satisfy the Authority regarding its claim of Market Economy Treatment. The non-confidential version of the exporter is grossly inadequate and insufficient to allow any understanding of the substance of information filed by the exporter. In the note to the notification No. 28/2001-Customs (N.T.), China has been listed amongst the non-market economy countries.

#### **VIEWS OF EXPORTER/PRODUCER(NEW SHIPPER)**

49. Views of exporter and producer (new shipper) have been summarised below:

50. The new shipper has claimed market economy treatment (MET) and has submitted evidence to substantiate the same.

- i) Bankruptcy Law of Peoples Republic of China, PR has an appropriate legal and regulatory framework for the operation of the firms and the firms can freely be declared bankrupt according to the related laws and regulations.
- ii) The major raw materials required for the manufacture of CFL is available in China PR. Company is free to procure the raw materials and other relevant inputs from the open market based on market prices set by demand and supply. No state or local authority has any say, in any manner, in setting the prices or costs of the raw material or the final product. There are no restrictions or conditions, either direct or indirect, on imports of raw materials used but the company not imported any raw materials from abroad.
- iii) The utilities are charged at normal rates without any special or subsidized rates. Electricity is being supplied by the State owned company however, water is supplied by private company. Water and electricity have been charged according to the consumption pattern and the prevailing prices charged by the concerned supply companies.
- iv) As regard to labour, firms have the freedom to organize and remunerate their labour. The only condition is that the firm has to ensure that the minimum wage levels are guaranteed. The company provides the housing facilities to the workers in the factory.
- v) According to the accounting principles in China, the firm has to maintain basic accounting records and the firms have their accounting records audited by independent auditing firms. The normal corporate financial accounting period is from January to December. The accounting practices of the applicants are in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of China
- vi) Land, buildings and machines are used for the production and commercial purposes. The company owns these facilities. Chinese laws protect property ownership. Natural and legal persons have the right by law to possess, utilize, profit from and dispose of his property. The General Principles of the Civil Law of People's Republic of China stipulates that an owner has rights to lawfully possess, utilize, profit from and dispose of his property. Thus, firms are subject to both bankruptcy and property laws, which guarantee the legal stability and certainty for the operations of business.
- vii) The company has never been involved in barter-trade or counter-trade. The company has never been involved in compensation trade (also known as product buy-back).

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

51. The Designated Authority, as per para 8(2) of Annexure I of the AD Rules for the purpose of determination of Normal Value, proceeded with a presumption that any country that has been determined to be or has been treated as, a non-

market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non-market economic country. In the past three years WTO members such as EU and USA have treated China PR as a non-market economy country in anti- dumping investigations. In the instance case, China PR has been proposed to be investigated as non-market economy Country.

52. The Authority sent Market Economy Treatment (MET) questionnaire and exporter's questionnaire to M/s. Osram China Lighting Co. Limited, China PR (Exporter). They filed the response in support of their claim of market economy treatment and requested for determination of normal value on the basis of domestic sales of subject goods in their home market. In view of their claim of MET treatment, verification was carried out at the premises of the responding producer and exporter. The Chinese producer has claimed individual treatment on the grounds that they are operating under market economy condition irrespective of prevailing economy situation in the country without any direct or indirect State interference or influence in their business activity.

53. In anti-dumping investigations normal value concerning imports originating in China PR, shall be determined in accordance with para 7 & 8 of Annexure I of the AD Rules. The Authority notes that para 7 of Annexure 1 of AD Rules provides that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin."*

54. Further Para 8 of Annexure 1 of the AD Rules (as amended) provides that:

- (1) *"8 (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph(3)*
- (2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economic country;*
- (3) *Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption*

*by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)."*

55. It is noted that the responding Chinese producer furnished information/evidence as mentioned in para 8(3) of Annexure 1 of AD Rules to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether

- a) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment v/a compensation of debts; such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;
- e) Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

56. Detailed questions regarding ownership, management, control, determination of commercial and business policies and on financial situation etc. were addressed to the applicant. Responses filed by the new shipper were analyzed to determine whether the applicant exercised a degree of independence from the Chinese Government comparable to what would prevail in a market economy country. The Authority sought general and certain specific information with regard to the following parameters from the applicants:-

- Ownership details
- Shareholding patterns
- Information on promoter/holding company/companies
- Constituents of Board of Directors, their legal status and person/party being represented by them.
- Raw Material Inputs and Costs
- Existence or otherwise of any minimum wage stipulation by the State and if the enterprises are free to decide wages as per market demand.
- Production Facilities and Costs
- Loans and subsidies
- Barter Trade/ Counter Trade
- Profit Distribution

- Bankruptcy and property laws
- Exchange rates conversions

57. In order to examine whether there was any degree of State influence or interference over the allocation of resources and decisions of the applicant, whether directly or indirectly, the ownership pattern of the petitioner was examined. The claims/ counter claims made by the interested parties were taken into account and details in this respect were verified. As per business license, the company is whole owned foreign enterprise in which a very high percentage of shares are held by M/s Osram GmbH and small percentage are held by M/s Prosperity Lamps & Components (HK) Ltd. Originally M/s Osram china Lighting Ltd. was held by three shareholders in which majority of shares were held by M/s Osram GmbH, however, subsequently Osram GmbH consolidated position by purchasing the share of the other company. The Authority notes that all members of board of directors are foreign nationals. The Authority examined the composition of Board of Directors of the company, their functions, to determine whether there is any interference and involvement of the State in the management and working of the companies. The Authority relied upon the relevant provisions relating to constitution of Board of Directors, Board of Supervision, General Manager, their functions & powers, appointment & dismissal, autonomy of the company in matters of appointment etc and the role which State or State owned/controlled persons/bodies plays, if any, in such companies whether directly or indirectly.

58. It was found that the raw materials were purchased from the open market and at market values as the prices of the various raw materials were varying and procured at market prices. It was found that the company procures an important raw material from one of the affiliates/related company in China PR. During the period of investigation the related party has not sold the said raw material to any other independent buyer. Accordingly the exporter was asked to obtain details of the cost of production of the said raw material from the affiliate company so as to establish that the transfer price represents a fair price. Copies of the same were submitted by the exporter after verification. It is observed that the price charged by the related party is based on cost plus reasonable profit. The same has been considered to be representative.

59. The Authority notes that the company is buying electricity from State owned company. Since electricity procurement was from State owned enterprises, the Authority examined the tariff at which the company was getting electricity. Copies of invoices were collected and tariff paid by the company was ascertained. It was found that the electricity have been charged according to the consumption pattern and the prevailing prices charged by the concerned electricity/water supply company.

60. The company was found to be maintaining its accounts as per Generally Accepted Accounting Principles of China. The company maintains monthly profit & loss statement which is required to file profit & loss statement along with VAT filing. The profit & loss statement for each of the months of the investigation period was examined and cross verified with the profit & loss statement filed by the company along with its VAT return and a separate profitability of the subject

goods and other goods was found. Accounts of the company are audited regularly by the Auditors and no adverse comments were found in their Auditor Report with regard to the accounting practices followed by the company.

61. Bankruptcy and property laws were examined and found that the company is free to acquire property. The bankruptcy law is applicable to a firm when a firm becomes bankrupt and the details regarding settlement of the dues is governed by law maintained under bankruptcy law.

62. Exchange rate conversions were also verified from their books of accounts and found that the export remittances were converted into the Chinese currency as per the exchange rate prevailing on the date of transaction. During the verification visit the export invoices were verified to see whether the realized amounts are credited into their books of accounts. The Authority observed that exchange conversions have taken place at the existing rate, which was more or less stable.

In view of above mentioned information and verified facts, the Authority decides to determine normal value in accordance with Section 9(A)(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

### **NORMAL VALUE**

63. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
  - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)
  - (c) The Authority sent exporter questionnaire to M/s. Osram China Lighting Co. Limited, China PR(Exporter), for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act. In response to the questionnaire the new shipper filed the information in exporter questionnaire. They have exported three sizes of the CFL with choke and the information regarding the domestic sales in their home market has been provided. The normal value as per Section 9A (1) (c) is the comparable price of domestic sales of subject

goods in the ordinary course of trade for the like article, which is meant for consumption in the exporting country. They have also provided break up of costs of production of all the sizes/models/types of the subject goods that have been produced and exported to India during the period of investigation. The element wise cost of production was also verified from the books of account maintained by the company. An analysis of the profit and loss account of the company shows that the company has made an overall profit on the sale of subject goods during the period of investigation and calendar year. The Normal Value based on cost of production plus SGA and reasonable profit for these models/types of CFL with choke, has been considered to be the appropriate basis for assessing the Normal Value

64. As indicated above the company has exported different models/types of two sizes of CFL to India during the period of investigation. These models are types of CFL with choke. Based on the methodology explained above size wise/ model/type wise ex-factory normal value for these models/ types of CFL with choke is determined as under:

Sl No	Size /model/type of CFL	Normal Value(US\$ per Pc.)
1	T3 8 watts	***
2	T3 11 watts.	***
3	T3 14 watts.	***

### **EXPORT PRICE**

65. In response to the questionnaire, the exporter has furnished invoice-wise/ size-wise details of exports made to India during the period of investigation in Appendix-2. The exporter has also furnished copies of invoices in support of the same. Exports to India have been made at FOB basis to M/s Osram India Ltd., a related company. The exporter has claimed adjustments on account of expenses up to FOB level. The company has made sales to India to M/s Osram India Ltd., one of its affiliates. Expenses from FOB to India have been incurred by the said importer. Details from the importer in importer's questionnaire was solicited. Adjustment as claimed by the importer with regard to landing, transportation, insurance, Customs Duty paid etc., have been considered based on verified data and is proposed to be allowed to arrive at the ex-factory export price to India. Further Invoices raised by M/s Osram India Ltd. pertaining to Indian customers were verified and reconciled along with the adjustments claimed by them. Details regarding their claim of adjustments were verified during the course of verification from the records maintained by the Importer at Delhi. The ex-factory export price has been calculated after taking into account the verified data regarding adjustments. The size wise and model/type wise ex factory export price of subject goods comes to :-

Sl No	Size /model/type	Export Price (US\$ per Pc.)
1	T3 8 watts	***



<u>2</u>	T3 11 watts.	***
<u>3</u>	T3 14 watts.	***

### **DUMPING MARGIN**

66. After determining dumping margins by considering above mentioned normal values and export prices for different sizes/ models /types, the weighted dumping margin for Compact Fluorescent Lamps (CFL) has been determined. It has been found that the exporter has exported the subject goods below its Normal Value and the weighted average dumping margin has been determined as US \$ 0.16 per piece.

### **Recommendations of the Authority**

67. After considering the foregoing the Authority concludes that

i) Export price of Compact Fluorescent Lamps (CFL) produced and exported to India by M/s. Osram China Lighting Co. Limited, China PR is below its normal value during the period of investigation.

ii) The Authority, therefore, recommends that anti dumping duty US\$ 0.16 per piece be imposed on imports of Compact Fluorescent Lamps (CFL) falling under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 produced and exported to India by M/s. Osram China Lighting Co. Limited, China PR.

68. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority